

एमटीएनएल इफेक्ट प्राइवेट फोन भी हो सकते हैं डिस्टर्ब

नव भारत टाइम्स

नया संवाददाता : नई दिल्ली

एमटीएनएल अधिकारियों के असहयोग आंदोलन का असर प्राइवेट टेलिफोन उपभोक्ताओं पर भी गहरा जा सकता है। आंदोलनकारी अधिकारियों का कहना है कि संगठनकारों से इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। इससे एमटीएनएल नेटवर्क का इस्तेमाल करने वाले प्राइवेट टेलिफोन ऑपरेटरों को सेवाएं भी खत्म हो सकती हैं।

इन दिनों दिल्ली में एमटीएनएल के 16 लाख सैलरान, 20 लाख मोबाइल और फर्स्ट कनेक्शन और चार लाख डीएनएल के उपभोक्ता हैं। आर्टिस्ट फोरम और एमटीएनएल एंजिनियरिंग एसोसिएशन के महासचिव अशोक कुमार कौशिक के मुताबिक इस आंदोलन को पहले से पहले ही दिन एमटीएनएल की दिल्ली और मुंबई दोनों ही जगह 80 मोसमी सेवाएं खत्म हो गईं हैं। यूनियन को नहीं माली वाली तो संगठनकार से इसका असर प्राइवेट ऑपरेटरों के कनेक्शन पर भी पड़ सकता है। अधिकतर प्राइवेट ऑपरेटर एमटीएनएल का नेटवर्क इस्तेमाल करते हैं।

संगठनकारों की दिल्ली में एमटीएनएल के प्राइवेटों को फोन सेवाएं खत्म हो रही हैं। हालांकि कुछ जगह टेलिफोन कनेक्शन खल रहे थे लेकिन यूनियन नेताओं का कहना है कि संगठनकारों को जब यह आंदोलन तेज होगा तो बाकी सेवाएं भी गड़बड़ाए जा सकेंगी हैं। उनका कहना है कि वे नहीं चाहते थे कि आंदोलन से उपभोक्ताओं को नुकसान हो, इसी वजह से वे दिल्ली से मुंबई से दिल्ली और धरमों के जरिए एमटीएनएल सैलरानों को भजने में जुटे थे लेकिन अब एक सैनसिमेंट के कोर्ट ऑनलाइन रिफरेंस नहीं दिया।

आंदोलनकारी अधिकारियों का कहना है कि उनका विरोध एमटीएनएल के उस आदेश के खिलाफ है, जिससे एमटीएनएल के अधिकारियों का वेतन बढ़ने को बजट 4000 से 8000 रुपये तक बढ़ा दिया जाएगा। यूनियन का कहना है कि



लाइन खराब है...

- ▶ एमटीएनएल अफसरों का असहयोग आंदोलन आम से होना और तेज
- ▶ अधिकतर प्राइवेट ऑपरेटर करते हैं नेटवर्क की हेल्पिंग
- ▶ संगठनकार को टेलिफोन और इंटरनेट लाइनमें बुरी तरह प्रभावित रही
- ▶ दिल्ली घटने की बात पर अाराज हैं एमटीएनएल के अफसर

संगठनकारी कंपनियों में गया सैनसिमेंट लागू करने के साथ संगठनकारों ने जो शर्तें रखी थीं, उन्हें एमटीएनएल पूरा करता है लेकिन एमटीएनएल ने जो ऑर्डर जारी किए हैं, उससे उनके भते तो कम होगे ही, साथ ही मकान किएए भते में भी कमी आ जाएगी। मकान का घटा हुआ भत 2006 से लागू हो जाएगा। इस तरह से अगर उस भते हुए भते की कटौती हुई तो मिलने वाले साल का निष्ठा हुआ भत भी उन्हें पराम कम हो जाएगा। उनका कहना है कि इस आदेश का असर एमटीएनएल के दिल्ली और मुंबई के 8000 अफसरों पर पड़ा है। यही वजह है कि उन्हें इस आंदोलन के लिए मजबूर होना पड़ा है।